

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// ज्ञापन //

क्रमांक B/4608 / दो-15-28/87

जबलपुर, दिनांक 25/11/2020

प्रति,

समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मध्यप्रदेश।

विषय:- म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एल.एल.एम की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप वेतन वृद्धि स्वीकृति किये जाने बाबत।

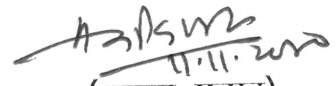
—000—

प्रायः देखने में आ रहा है कि, विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उनकी स्थापना में पदस्थ म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एल.एल.एम की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु रजिस्ट्री को प्रेषित किये जा रहे हैं।

चूंकि म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा पुस्तिका उनकी वर्तमान पदस्थापना में संघारित की जाती है तथा वेतनवृद्धि स्वीकृत संबंधी कार्यवाही भी आपकी स्थापना द्वारा ही की जाती है।

अतः समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुरोध है कि, आपकी स्थापना में कार्यरत म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एल.एल.एम की उपाधि धारण करने तथा रजिस्ट्री द्वारा उन्हें स्थायीकरण संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही आपके कार्यालय द्वारा की जावेगी।

संलग्न:- म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
के आदेश दिनांक 15.01.2010 की छायाप्रति।


(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

/आदेश/

भोपाल, दिनांक 15.1.2010

फा0कमांक 3(ए)19/2003/21-ब(एक) राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) कमांक 1022/89 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में, दिनांक 21 फरवरी, 2006 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, ऐसे न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने विधि में स्नात्कोत्तर डिग्री एल0एल0एम0 की उपाधि धारण की हो, को दिनांक 1.12.2009 से 3 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0कमांक 2326/09/नि/चार, दिनांक 12.1.2010 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के आनंद में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(एन0 के0 गुप्ता)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0क0 3(ए)19/2003/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक 15जन0,2010

प्रतिलिपि:-

1. याचिका के प्रभारी अधिकारी सचिव, म0 प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया पालन प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के सनक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. रजिस्ट्रार जनरल, म0 प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर
4. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म0 प्र0 उच्च न्यायालय, खांडपीठ, इंदौर / खालियर
5. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, ग्राम एवं नगरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, भोपाल

.....2/-

